REGISTERED No. D. 222

The Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 4, 1963/VAISAKHA 14, 1885

NOTICE

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published upto the 22nd April, 1963:—

Issue No.	No. and date	Issued by	Subject
55.	No. 4/63, dated 22nd April, 1963	Ministry of Commerce & Industry.	The Imports (Control) Third Amendment Order, 1963.
	No. 5/63, dated 22nd April, 1963.	Ditto.	The Imports (Control) Fourth Amendment Order, 1963.
	No. 6/63, dated 22nd April, 1963.	Ditto.	The Imports (Control) Fifth Amendment Order, 1963.

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	207
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court	187
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	Nil
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers, issued by the Ministry of Defence	151
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	Nil
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	Nil
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	871
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	1389
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	107
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India (*Published at Simla*)	449
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta (*Published at Simla*)	179
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners (*Published at Simla*)	67
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including notifications, orders, advertisements and notices issued by Statutory Bodies (*Published at Simla*)	147
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private bodies (*Published at Simla*)	55
SUPPLEMENT NO. 17—	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 27th April, 1963	317
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 6th April, 1963	324

PART I—Section 1

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th April 1963

No. 44-Pres./63.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Intelligence Bureau:—

Shri Tashi Tseten Samdup, Deputy Central Intelligence Officer, Intelligence Bureau.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

No. 45-Pres./63.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Intelligence Bureau:—

Shri Samten Tashi, Constable, Intelligence Bureau (*deceased*).

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible to officers of and below the rank of Inspector of Police as provided in rule 5, with effect from the 11th October, 1962.

No. 46-Pres./63.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Intelligence Bureau:—

Shri Kesang Lhendup, Constable, Intelligence Bureau.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible to officers of and below the rank of Inspector of Police as provided in rule 5, with effect from the 9th September, 1962.

No. 47-Pres./63.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Intelligence Bureau:—

Shri Yontan Zangpo, Junior Intelligence Officer, Intelligence Bureau.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible to officers of and below the rank of Inspector of Police as provided in rule 5, with effect from the 27th October, 1962.

No. 48-Pres./63.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Intelligence Bureau:—

Shri Baldev Prasad Sood, Head Constable (Technical), Intelligence Bureau.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible to officers of and below the rank of Inspector of Police as provided in rule 5, with effect from the 26th October, 1962.

S. DUTT, Secy.

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1963

सं० 44-प्रेज/63.—राष्ट्रपति इण्टेलिजेंस ब्यूरो के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

श्री ताशी त्सीतन समधुप, डिप्टी सेंट्रल इण्टेलिजेंस आफिसर, इण्टेलिजेंस ब्यूरो।

2. यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है।

सं० 45-प्रेज/63.—राष्ट्रपति इण्टेलिजेंस ब्यूरो के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

श्री समतेन ताशी, कान्स्टेबल, इण्टेलिजेंस ब्यूरो (मृत)।

2. यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है। और पुरस्कृत अधिकारी 11 अक्तूबर 1962 से विशेष भत्ते का हकदार होगा यदि नियम 5 के अनुसार उसका पद पुलिस इन्स्पेक्टर के पद से नीचा होगा।

सं० 46-प्रेज/63.—राष्ट्रपति इण्टेलिजेंस ब्यूरो के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

श्री केसांग लहेन्धुप, कान्स्टेबल, इण्टेलिजेंस ब्यूरो।

2. यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है। और पुरस्कृत अधिकारी 9 सितम्बर 1962 से विशेष भत्ते का हकदार होगा यदि नियम 5 के अनुसार उसका पद पुलिस इन्स्पेक्टर के पद से नीचा होगा।

सं० 47-प्रेज/63.—राष्ट्रपति इण्टेलिजेंस ब्यूरो के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

श्री योनतान यांगपो, जूनियर इण्टेलिजेंस आफिसर, इण्टेलिजेंस ब्यूरो।

2. यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है। और पुरस्कृत अधिकारी 27 अक्तूबर 1962 से विशेष भत्ते का हकदार होगा यदि नियम 5 के अनुसार उसका पद पुलिस इन्स्पेक्टर के पद से नीचा होगा।

सं० 48-प्रेज/63.—राष्ट्रपति इण्टेलिजेंस ब्यूरो के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

श्री बलदेव प्रसाद सूद, हैड कान्स्टेबल (टैक्निकल), इण्टेलिजेंस ब्यूरो।

2. यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है। और पुरस्कृत अधिकारी 26 अक्तूबर 1962 से विशेष भत्ते का हकदार होगा यदि नियम 5 के अनुसार उसका पद पुलिस इन्स्पेक्टर के पद से नीचा होगा।

सुबिमल दत्त,
राष्ट्रपति का सचिव।

सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय

(सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली मार्च 30, 1963

संख्या 7.8/62-कोर्ड.—श्रम ठेका और निर्माण सहकारी समितियों की अखिल भारतीय गोष्ठी, जो नागपुर में सितम्बर 1962 में हुई थी, ने सिफारिश की थी कि देशभर में श्रम सहकारी समितियों के विकास के लिए व्यापक नीतियां निर्धारित करने और उपयुक्त योजनाएं और कार्यक्रम बनाने के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों और श्रम सहकारी समितियों के संघों के प्रतिनिधि हों। राज्य के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन, जो लखनऊ में फरवरी 1963 में हुआ था, ने भी गोष्ठी की इस सिफारिश की पुष्टि की। भारत सरकार ने तदनुसार श्रम ठेका और निर्माण सहकारी समितियों के एक राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है।

2. बोर्ड का गठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

(1) सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्री

उपाध्यक्ष

(2) उपमंत्री (सहकारिता), सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय

सदस्य

(3) श्री ई० पी० पोल्स, सहकारिता के कार्यकारी मंत्री, केरल राज्य, त्रिवेंद्रम

(4) श्री डी० जे० नायक, संसद सदस्य, 83, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली

(5) श्री एस० एन० द्विवेदी, संसद सदस्य, 21, कैनिंग लेन, नई दिल्ली

(6) श्री ईश्वर दास बगूर, अध्यक्ष, दिल्ली राज्य श्रम ठेका और निर्माण सहकारी समिति संघ, दिल्ली

(7) श्री ई० वी० रामरेड्डी, अध्यक्ष, श्रम ठेका और निर्माण सहकारी समिति संघ, हैदराबाद

(8) श्री रत्न चंद, प्रधान, पंजाब राज्य सहकारी श्रम और निर्माण समिति संघ, पंजाब

(9) श्री एल० एन० भोंगीरवार, रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, महाराष्ट्र, पूना

(10) श्री एम० एल० बत्तरा, मुख्य अधिकारी, ग्रामीण ऋण अनुभाग, स्टेट बैंक आफ इन्डिया

(11) श्री वी० के० राव, संयुक्त सचिव, निर्माण, आवास और शहरी मंत्रालय, नई दिल्ली

(12) श्री एम० के० विदवाई, संयुक्त सचिव, सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली

(13) श्री डी० जी० जाधव, सलाहकार (श्रम तथा कल्याण) रेलवे बोर्ड

(14) श्री एम० आर० भिडे, सचिव, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय, नई दिल्ली

सदस्य-सचिव

(15) श्री जी० डी० गोस्वामी, संयुक्त सचिव, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।

3. बोर्ड के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) श्रम सहकारी समितियों के कार्यक्रम की प्रगति का पुनरावलोकन करना ।

(2) कार्यक्रम में श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने और उनकी पहल करने तथा नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना ।

(3) कार्यक्रम को चलाने के लिए अपेक्षित कार्यकर्ताओं की शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रबन्धों के बारे में सुझाव देना ।

(4) राज्य सरकारों की श्रम सहकारी समितियों के बारे में उनकी अपनी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में सहायता करना ।

(5) ऐसे दूसरे उपाय अपनाना जो बोर्ड के विचारणीय विषयों के अनुसार सुसंगत हों ।

4. आकस्मिक रिक्तियां उस प्राधिकारी या निकाय की सलाह से भरी जाएंगी जिसने स्थान रिक्त करने वाले सदस्य को मनोनीत किया था ।

5. बोर्ड की बैठकें समय समय पर होती रहेंगी और 6 महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी ।

7. यह बोर्ड 2 वर्षों के पश्चात पुनर्गठित किया जाएगा ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश है कि यह संकल्प भारतीय राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

(सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली अप्रैल 15, 1963

संख्या एफ० 11.19/63-कोर्ड.—तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी विकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम है । इस विस्तृत कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक कुशल सहकारी प्रशासन की आवश्यकता होगी जिसमें पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारी हों । राज्यों के सहकारी मंत्रियों का जो सम्मेलन लखनऊ में फरवरी, 1963 को हुआ था उसमें इस प्रश्न पर विचार किया गया था और सिफारिश की गई थी कि राज्यों में सहकारी प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए । भारत सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है और निम्न प्रकार से एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है :—

अध्यक्ष

1. श्री बी० एल० मेहता,

सदस्य

2. श्री जी० डी० गोस्वामी, संयुक्त सचिव, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय

3. श्री कम्बेकर, मुख्य अधिकारी, कृषि ऋण विभाग, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया

4. श्री एम० एल० बत्तरा, ग्रामीण ऋण अधिकारी, स्टेट बैंक आफ इन्डिया

5. श्री आर० दशरथराम रेड्डी, एम० एल० ए०, प्रधान, आंध्र राज्य सहकारी बैंक

सचिव

6. श्री जी० वी० रामामूर्ती, सहायक मुख्य अधिकारी, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया ।

2. समिति के विचारणीय विषय नीचे दिये जाते हैं :—

(क) विभिन्न राज्यों में वर्तमान विभागीय ढांचे का पुनरावलोकन करना और विभिन्न स्तरों अर्थात् मुख्यालय, डिवीजनल, जिला और नीचे के स्तरों, के कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए व्यापक सिद्धांत सुझाना,

(ख) सहकारी खेती, सहकारी क्रय-विक्रय, विधायन, औद्योगिक समितियों और अन्य प्रकार की समितियों जैसी कार्य की विशिष्ट मदों के बारे में कार्य करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक विशिष्ट कर्मचारियों के विषय में सिफारिश करना,

(ग) विभिन्न स्तरों के लेखा परीक्षक कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने के मापदण्ड के बारे में सिफारिश करना,

(घ) पर्यवेक्षकों की संख्या निश्चित करने के मापदण्ड के बारे में सुझाव देना चाहे वे सरकार, सहकारी संघों द्वारा रखे गए हों या धन सुलभ करने वाले बैंकों द्वारा जैसी भी स्थिति हो,

(ङ) विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपाय सुझाना; और

(च) नीतियों और कार्यक्रमों में अधिरतता लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर भर्ती के लिए व्यापक कार्यप्रणाली सुझाना।

3. समिति जानकारी एकत्रित करने और सरकारी व गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर सकती है।

4. समिति का मुख्यालय बम्बई में होगा।

5. समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट देगी।

एम० आर० भिड़े, सचिव।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd April 1963

No. 20/5(S)/63-Est(B).—The President has been pleased to appoint Shri Batuk Singh as Member of the Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 19th April, 1963.

B. D. JAYAL, Dy. Secy.

MINISTRY OF STEEL & HEAVY INDUSTRIES

(Deptt. of Iron and Steel)

ORDER

New Delhi, the 24th April 1963

No.P&D-9(48)/61-RM.—The Government of India hereby direct that the following amendments shall be made to the Order regarding the appointment of members of the Standing Committee on Raw Materials for the Steel Industry, No. SC(A)-24(45)/60-DEV dated 1st November, 1960, namely:

For the existing entries No. 10 and 15.

"Read:—10—Mr. R. H. Wright, M/s. Andrew Yule & Co. Ltd., 8-Clive Row, Calcutta-1.

15—Shri Pran Prashad, Bird and Co. (P) Ltd., Chartered Bank Buildings, Calcutta-1".

P. SEN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY.

(Department of International Trade)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th April 1963

Committee on Commercial Arbitration

No. 20(2)63-B.O.T.—The Board of Trade has recommended that a committee be appointed to review the existing arrangements for arbitration of commercial disputes arising in the course of foreign trade and to recommend appropriate measures for their improvement so as to facilitate the development of India's export trade on a sustained and enduring basis. The Government accept the recommendation of the Board of Trade and have accordingly decided to appoint a committee for this purpose.

2. The Committee will consist of the following:—

Chairman

(1) Shri B. T. Merchant, Government Solicitor and *Ex-officio*. Jt. Secretary to the Government of India, Department of Legal Affairs, Ministry of Law, New Delhi.

Members

(2) Dr. K. Krishna Rao, Director, Legal and Treaties Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.

(3) Shri H. D. Shourie, Joint Secretary, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.

(4) Shri K. M. Mirani, Deputy Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(5) Shri K. P. U. Menon, Director, State Trading Corporation of India Ltd., New Delhi.

(6) Shri N. Krishnamurthi, Deputy Secretary, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, New Delhi.

(7) Shri S. Subramaniam, Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.

3. Shri M. L. Gupta, Under Secretary, Ministry of Commerce and Industry, will be the Secretary of the Committee.

4. The terms of reference of the Committee will be as follows:—

(a) To study the special provisions that exist for arbitration of commercial disputes arising in the course of foreign trade in respect of various commodities and make recommendations for their improvement;

(b) to review the adequacy of the existing arrangements for arbitration of commercial disputes in respect of commodities not covered by such special provisions and make recommendations for their augmentation or improvement;

(c) to study the existing commercial practices in regard to the settlement of disputes arising in the course of foreign trade with particular reference to:—

(i) incorporation of an arbitration clause in trade contracts;

(ii) place of arbitration; and

(iii) agency of arbitration;

and to suggest such modifications thereto as may be necessary to render them more effective and more equitable;

(d) to review, in the light of international conventions, the scope and application of the present Indian law on commercial arbitration with particular reference to the enforcement of arbitration awards and determine the extent to which it requires to be amended in order to render it an effective instrument for expeditious settlement of commercial disputes;

(e) to study the adequacy of organisations engaged in the arbitration and settlement of commercial disputes and their working and specify the extent to which they require to be supplemented or strengthened; and

(f) to generally review the whole field of existing arrangements for the settlement and arbitration of commercial disputes arising in the course of foreign trade and to make recommendations for their improvement so as to facilitate development of export trade on a sustained and enduring basis.

5. The Committee may meet at New Delhi or other important trade centres in the country.

6. The Committee will submit its report to the Government within three months.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. PRASAD, Jt. Secy.

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1963

सं० 18(4)-प्रो०/62.—राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के जो कि संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अधीन एक संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो गई है नियमों के नियम 3 के अधीन भारत सरकार में जो शक्तियां निहित हैं उनके सामर्थ्य से और इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 18(2)-प्रो०/60 तारीख 10 अक्तूबर, 1960 का भागतः रूपभेदन करते हुए, भारत सरकार श्री एच० वी० आर० आयंगर को 18 फरवरी 1963 के अपरान्ह से डा० पी० एस० लोकनाथन के स्थान में जिसने कि उसी तारीख से त्यागपत्र दिया है उक्त नियम के खंड (क) के अधीन एतद्द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के शासीनिकाय का अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करती है।

संख्या 7(1)मंटा/63.—भारत के धातु निगम को देय जस्ते का मूल्य संकल्प सं० 15(15)मंटा/58, दिनांक 5 दिसम्बर, 1959 में घोषित जिसका संशोधन संकल्प सं० 15(1)मंटा/60, दिनांक 22 अप्रैल, 1961 में किया जा चुका है, उस समय तक, प्रवृत्त रहेगा, अब तक कि निगम को अपने पिघलावक में, जिसके संस्थापन के लिये उद्योग (वि० तथा वि०) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस दिया जा चुका है अथवा 31 मार्च 1964 तक, जो भी पहले हो, परिष्करण के लिए जस्ते का स्टाक एकत्र नहीं कर लिया जाता।

एन० चिदम्बरम्, उप-सचिव।

MINISTRY OF SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS

New Delhi, the 4th May 1963

No. 23(3)/56-SRII.—On the recommendation of the Scientific Advisory Committee to the Cabinet, the Govt. of India have decided to set up a National Committee for Biochemistry consisting of the following:—

Chairman

(1) Dr. V. Subrahmanyan, Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore.

Members

(2) Dr. P. S. Sarma, Professor of Biochemistry, Indian Institute of Science, Bangalore.

(3) Shri P. B. Kurup, Managing Director, Technochemical Industries Ltd., Calicut.

(4) Dr. A. R. Sundarajan, Professor of Biochemistry and Nutrition, All Indian Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta.

(5) Dr. B. K. Bachhawat, Associate Professor of Biochemistry and Research Biochemist, Neurochemistry Laboratory, Deptt. of Neurology and Neurosurgery, Christian Medical College and Hospital, Vellore.

(6) Dr. O. Siddiqui, Tata Institute of Fundamental Research, Bombay.

2. The objects of the Indian National Committee for Biochemistry will be to realise the objects of the Union which are as follows:—

(a) to encourage the continuance of a series of International Congresses of Biochemistry;

(b) to promote international co-operation of research, discussions and publications;

(c) to organise permanent co-operation between the societies representing biochemistry in the adhering countries; and

(d) to contribute to the advancement of biochemistry in all its international aspects.

H. K. L. CHADDHA, Under Secy.

New Delhi, the 27th April 1963

No. F. 16-130/61-SIII.—The President is pleased to decide that the following posts in the Botanical Survey of India be redesignated as shown below with immediate effect:—

Present designation	*Revised designation*
(1) Chief Botanist.	Director.
(2) Director, Central Botanical Laboratory.	Joint Director.
(3) Deputy Chief Botanist.	Deputy Director.
(4) Superintendent, Indian Botanic Garden.	Deputy Director.

S. K. SANYAL, Under Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

(Department of Transport)

(Transport Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd April 1963

No. 24-MT(29)/61.—In pursuance of the Government of India, Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) Resolution No. 24-MT(6)/52, dated the 17th August, 1959 and No. 24-MT(6)/52, dated the 18th July, 1961, the Central Government constituted the Merchant Navy Training Board for a period of two years with effect from the 29th October 1959. On the expiry of the said period of two years, the life of the Board was extended for a further period upto the end of June, 1962. The life of the Board having expired on the 1st July, 1962, the Central Government has been pleased to reconstitute the Board for a period of two years with effect from the date of this Resolution and to appoint the following persons on the Board:—

President

Minister of Shipping.

Chairman

Additional Secretary to the Government of India and Director General of Shipping.

Vice-Chairman

Senior Deputy Director General of Shipping.

Members

1	Shri M. P. Bhargava	Member of Parliament
2	Shri V. R. Dafle	Member of Parliament
3	Dy. Secretary to the Government of India, Ministry of Transport & Communications, Department of Transport, dealing with the training institutions	Ex-officio.
4	Dy. Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Communications Division).	Do.
5	Nautical Adviser to the Government of India	Do.
6	Chief Surveyor with the Government of India	Do.
7	Principal, Nautical and Engineering College, Bombay	Do.
8	Captain Superintendent, Training Ship "DUFFERIN", Bombay	Do.
9	Director, Marine Engineering Training, Calcutta	Do.
10	Shri N. K. Kershaw, Captain Superintendent, Training Ship "MEKHALA", Vishakhapatnam.	Do.
11	Shri G. K. Chandiramani, Joint Education Adviser, (Technical).	Representative of the Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs.
12	Captain M. L. Barua, I.N., Director of Naval Plans.	Representative of Naval Headquarters.
13	Shri A. C. Roy, Principal, Bengal Engineering College, Sibpur, Howrah.	Representative of the All India Council of Technical Education.
14	Shri C. P. Srivastava, Managing Director, Shipping Corporation of India.	Representative of the Shipping Corporation of India.
15	Shri P. N. Batra, Assistant Conservator, Commissioners for the Port of Calcutta.	Representative of the Port Trusts.
16	Smt. Sumati Morarjee	Representatives of the Indian National Steamship Owners' Association.
17	Shri J. M. Kapadia	
18	Capt. T. W. Stokoe of Caltex (India) Ltd.	Representative of Calcutta Liners Conference/Owners' Agents Committee (Crews).
19	Shri J. D. Randeri	Representative of the Maritime Union of India.
20	Shri Pratap Sinh Vallabhdas.	Representative of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.
21	Shri I. B. Syed	Representative of Seamen.

The principal, Nautical and Engineering College, Bombay, will act as Member-Secretary of the Board.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Planning Commission, all the Ministries of the Government of India, all the State Governments, the port Trusts, Bombay and Madras, the Port Commissioners, Calcutta, the Cochin Harbour Authority, the Vishakhapatnam Port Authority and the Director General of Shipping, Bombay.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NAGENDRA SINGH, Additional Secy.

परिवहन तथा संचार मंत्रालय

(परिवहन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1963

संख्या : 24-एम०टी०(29)/61.—भारत सरकार, परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) के संकल्प संख्या 24-एम०टी०(6)/52 दिनांक 17 अगस्त 1959 और संख्या 24-एम०टी०(6)/52 दिनांक 18 जुलाई 1961 के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने 29 अक्तूबर 1959 से दो वर्ष के लिए व्यापारी बेड़ा प्रशिक्षण बोर्ड (Merchant Navy Training Board) का गठन किया था। दो वर्ष की इस अवधि के समाप्त होने पर बोर्ड की अवधि 1962 जून के अंत तक बढ़ाई गयी थी। इस अवधि के पहली जुलाई 1962 को समाप्त होने पर केन्द्रीय सरकार सहर्ष बोर्ड का पुनर्गठन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष के लिए करती है और उस में निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति करती है :—

प्रधान

मंत्री जहाज़रानी

अध्यक्ष

भारत सरकार के अपर सचिव और जहाज़रानी के महानिदेशक

उपाध्यक्ष

जहाज़रानी का वरिष्ट उप महानिदेशक

सदस्य

1. श्री एम० पी० भार्गव, संसद् सदस्य
2. श्री बी० आर० दाफली, संसद् सदस्य
3. प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्ध रखने वाला उप सचिव, भारत सरकार, परिवहन तथा संचार मंत्रालय, परिवहन विभाग पदेन
4. उप सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (संचार प्रभाग) ,,
5. भारत सरकार का नौ सलाहकार ,,
6. भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक ,,
7. प्रिंसिपल, नौ इंजीनियरिंग कालेज, बंबई ,,
8. कप्तान अधीक्षक, प्रशिक्षण पोत 'डफरिन, बंबई ,,
9. निदेशक, समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण, कलकत्ता पदेन
10. श्री एन० के० केरशो, कप्तान, अधीक्षक प्रशिक्षण पोत 'मेखला', विशाखापतनम ,,
11. श्री जी० के० चण्डीरमानी, संयुक्त शिक्षा सलाहकार (प्राविधिक) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि
12. कप्तान एम० एल० बरुआ, आई० एन० एन० नौसेना-योजनाओं के निदेशक नौसेना हेडक्वार्टर के प्रतिनिधि
13. श्री ए० सी० राय, प्रिंसिपल, बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, सिबपुर, होड़ा प्राविधिक शिक्षा को अखिल भारतीय परिषद् के प्रतिनिधि
14. श्री सी० पी० श्रीवास्तव, प्रबन्ध निदेशक, भारत का नौपरिवहन आयोग भारत के नौपरिवहन आयोग के प्रतिनिधि
15. श्री पी० एन० बत्रा, सहायक संरक्षक कलकत्ता पत्तन के आयुक्त पोर्ट ट्रस्टों के प्रतिनिधि
16. श्रीमती सुमति मुरारजी
17. श्री जे० एम० कपाडिया

भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संस्था के प्रतिनिधि

18. कप्तान टी० डब्ल्यू० स्टोकोई, कालटेक्स (इण्डिया) लिमिटेड कलकत्ता लाइनर्स कांफरेंस । मालिक एजेंट समिति (कर्मी-दल) के प्रतिनिधि
19. श्री जे० डी० रांडेरी मेरिटाइम युनियन आफ इण्डिया के प्रतिनिधि
20. श्री प्रताप सिंह बल्लभदास वाणिज्य और उद्योग के भारतीय मण्डलों के संघ के प्रतिनिधि
21. श्री आइ० वी० सैंद नाविकों के प्रतिनिधि ।

नाविक तथा इंजीनियरिंग कालेज, बम्बई के प्रिंसिपल बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति राष्ट्रपति के सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, मंत्रिमंडल के सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पोर्ट ट्रस्ट, बम्बई और मद्रास, पत्तन आयुक्त, कलकत्ता, कोचीन बन्दरगाह अधिकारी, विशाखापत्तनम बन्दरगाह अधिकारी और जहाजरानी के महानिदेशक बंबई, को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

नागेन्द्र सिंह, अपर सचिव।